reports indicating that some ULFA militants are getting training and other assistance from across the border in Bangladesh.

(c) Yes, Sir.

(d) Government of Bangladesh have categorically denied having given any assistance to ULFA or the presenec of ULFA bases in Bangladesh.

(e) and (f) This is a bilateral matter under discussion between the Governments of India and Bangladesh.

Indian Airlines booking office at Vijayawada

*50. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian Airlines booking office at Vijayawada is not booking for Vayudoot flights, even though Vijayawada is not connected by Indian Airlines; and

(b) what is the purpose for continuance of the booking office if they are not allowed to book for Vayudoot?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAV RAO SCINDIA): (a) and (b) Indian Airlines Booking Office at Vajayawada issues tickets for Vayudoot flights to|from Vijayawada provided such flights are in conjunction with travel on Indian Airlines services.

Setting up of a Tourist Complex at Rameshwaram

*51. SHRI M. VINCENT: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a tourist complex at Rameshwaram in Tamil Nadu to attract more foreign tourists;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if not, whether Government are considering to give financial assistance to the State to set up the complex?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAV RAO SCINDIA): (a) and (b) Development of tourism is primarily the responsibility of the State Governments. However, the Central Department of Tourism extends financial assistance on specific projects|schemes received from them and depending upon their merit, availability of funds and *inter-se* priorities.

In order to attract more foreign tourists to Rameshwaram, the Department of Tourism have sanctioned an amount of Rs. 18.45 lakhs during the Seventh Five Year Plan for the construction of a Tourist Reception Centre with accommodation facilities and Rs. 01.50 lakh during 1990-91 for upgradation of facilities in Hotel Tamil Nadu,, Rameshwaram. No project proposal for Rameshwaram has been received from the State Government during 1991-92.

(c) Does not arise.

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम का कार्यकरण

*52. डा. जितेन्द्र कुमार जैन :
श्री राम जेठमलानी :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम कतिपय जल-मार्गों द्वारा माल की ढुलाई करता है ;

(ख) यदि हां, तो निगम के पास कितने पोत हैं ;

(ग) कार्यरत पोतों की संख्या कितनी है ;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निगम द्वारा ढोए गए माल की प्रमात्रा का वर्षवार ब्यौरा क्या है और उसी अवधि के दौरान उसे वर्षवार कितना-कितना घाटा हुआ; और

(ङ) क्या सरकार निगम को हो रहे निरन्तर घाटे को ध्यान में रखते हुए वर्तमान व्यवस्था से आमूल परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री **(श्री जगदीश टाइटलर)** : (क) जी, हां ।

(ख) 158 जहाज

(ग) 134 जहाज

(करोड़ रु०)

(घ) वर्ष	ढाया गया कार्गो (टन)	सामग्री के परिवहन में प्रचालन घाटा
1988–89	3,04,356	4.90
1989–90	4,10,331	4.37
1990–91	3,35,412	6.23 (अनंतिम)

(ङ) पुराने तथा गैर मरम्मत योग्य जहाजों की स्क्रैपिंग करके जहाज-बेड़े का आधुनिकीकरण किया जा रहा है । कार्गो क्षमता जो कि 1985–86 में 4.15 लाख टन थी, 1990–91 में बढ़ कर 5.2 लाख टन हो गई है । पहले ही आर्डर दिए जा चुके शेष जहाजों की डिलीवरी के पश्चात् यह बढ़ कर लगभग 10 लाख टन हो जाएगी ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन के जहाजों को बंगला देश से होकर कलकत्ता से उत्तर-पूर्व जाने की अनुमति देने के लिए बंगला देश के साथ 4–10–91 से 2 वर्ष की और अवधि के लिए समझौते का नवीनीकरण किया गया है ।

गैर-सरकारी द्वारा चलायी जाने के कारण दिल्ली परिवहन निगम को हो रहे घाटे

*53. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री वीरेन जे० शाह :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अगस्त, 1991 के "इकॉनामिक टाइम्स" में "डी०टी०सी० इन्कर्स मेजर लासिज आन किलोमीटर स्कीम सी०ए०जी० रिपोर्ट" शीर्षक के अधीन प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस स्कीम के अधीन गैर-सरकारी बसों के चलाए जाने से संबंधित अपनी नीति की समीक्षा की है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जुलाई, 1989 में सरकार ने ऐसी एक वैकल्पिक स्कीम जिसके अधीन और गैर-सरकारी स्वामित्व की बस लाभ में चलायी जा सके, की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ङ) यदि नहीं तो इस प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ; और